भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 559

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

हरियाणा में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

†*559. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षेत्र में यात्रियों की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते आर्थिक कार्यकलापों को देखते हुए सरकार की दिल्ली-रोहतक-हिसार और दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो व्यवहार्यता अध्ययन की वर्तमान स्थिति, राज्य सरकारों के साथ परामर्श और ऐसे विस्तार के लिए विचाराधीन समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली की भीड़भाड़ को कम करने, क्षेत्रीय आवागमन में सुधार और हरियाणा में संतुलित शहरी विकास के लिए ऐसे आरआरटीएस विस्तार के संभावित लाभों की पहचान की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावित विस्तारों के लिए वित्तपोषण, भूमि की उपलब्धता, यात्रियों की संख्या के अनुमान और अन्य तकनीकी मापदंडों के संबंध में हरियाणा की राज्य सरकार के साथ हुई किसी भी चर्चा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"हरियाणा में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम" के संबंध में श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछे गए 02 अप्रैल, 2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 559 (स्थिति 19वां) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने 'एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर एक कार्यात्मक योजना' तैयार की है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल आधारित कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को सेमी-हाई स्पीड रेल आधारित कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ने के लिए आठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर की पहचान की गई है, नामत: (1) दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर (ii) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (iii) दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (iv) दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल (v) दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक (vi) दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत (vii) गाजियाबाद-खुर्जा और (viii) गाजियाबाद-हापुड़।

भारत के पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा नियुक्त कार्य बल ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन आरआरटीएस कॉरिडोर को प्राथमिकता दी थी:

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ
- दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर
- दिल्ली-पानीपत

82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को केंद्र सरकार द्वारा मार्च, 2019 में ही मंजूरी दी जा चुकी है और यह पूरी तरह से चालू है।

वर्तमान में, संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा दिल्ली-रोहतक-हिसार और दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल के बीच आरआरटीएस कनेक्टिविटी के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

नमो भारत ट्रेनों को 160 किमी/घंटा की परिचालन गति के साथ 180 किमी/घंटा की उच्च गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार से प्राप्त लाभों में बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, सड़कों की भीड़भाड़ कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी, कुशल और अकुशल नौकरियों का सृजन और यात्रा के समय में कमी शामिल है।

****